दैनिक भारत कि
तामीर
संपादक - काझी मकदूम शफीउद्दीन hinditameer@gmail.com

ससून अस्पताल की रिपोर्ट अस्वीकार्य, इसे आग के हवाले कर देना चाहिए-सुप्रिया सुले

पुणे (अज़ीज़ अइजाज़)

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) की राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद सुप्रिया सुले ने ससून अस्पताल की रिपोर्ट को लेकर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल में हुई घटना की जो रिपोर्ट सामने आई है, वह पूरी तरह भ्रामक और अस्वीकार्य है। यह रिपोर्ट पीड़िता और उसके परिवार के जख्मों पर नमक छिड़कने के समान है। हम इस रिपोर्ट को पूरी तरह खारिज करते हैं। बल्कि मैं कहना चाहूंगी कि ऐसी रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में फेंक देना चाहिए या फिर आग के हवाले कर देना चाहिए। पुणे में पत्रकारों से बात करते हुए सुप्रिया सुले ने कहा कि दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल और डॉक्टर घीसास को बचाने के लिए जानबूझकर पक्षपातपूर्ण रिपोर्ट तैयार की गई है। हमारी पार्टी के सहयोगी प्रशांत जगताप इस मामले को लेकर २४ अप्रैल को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने जा रहे हैं, इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करती हूं। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर एक बेटी, पत्नी या मां की मौत के बाद भी सरकार इतनी संवेदनहीन बनी रहती है और सच्चाई को छुपाने वाली रिपोर्ट तैयार करती है, तो यह अत्यंत चिंताजनक और निंदनीय है।

बीड (महाराष्ट्र) | वर्ष-१ ला | अंक-२६० वा | रविवार २० एप्रिल २०२५ | RNI TITLE CODE:MAHHIN11405/120/1/3/2024 | किमत : २ रूपये | पन्ने - ४

महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड का पहला मेडिकल कॉलेज बीड़ में स्थापित होगा: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसने दी मंजूरी

बीड़ (प्रतिनिधि)

महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड द्वारा राज्य का पहला मेडिकल कॉलेज अब बीड़ जिले में स्थापित किया जाएगा। इस आशय का निर्णय कुछ ही दिन पूर्व मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया था। आज बीड़ दौरे पर आए मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश देकर इस निर्णय पर औपचारिक मुहर लगा दी। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष समीर काज़ी ने जानकारी दी कि यह प्रस्ताव मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्णय और उपमुख्यमंत्रियों एकनाथ शिंदे तथा अजित पवार के सहयोग से संभव हो पाया है। उन्होंने बताया कि बीड़ में वक्फ बोर्ड का मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए उन्होंने प्रारंभ से ही सतत प्रयास किया था, जो अब सफल होते दिख रहे हैं।

मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार अब सबसे पहले बीड़ में वक्फ बोर्ड की किसी उपयुक्त भूमि का चयन किया जाएगा। इसके बाद वक्फ बोर्ड की ओर से प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा। इस प्रक्रिया में स्वास्थ्य विभाग से भी विमर्श किया जाएगा और अंतिम प्रस्ताव को आगे भेजा जाएगा। महाराष्ट्र सरकार की ओर से वक्फ बोर्ड को इस परियोजना में भरपूर सहयोग मिलेगा।

वक्फ बोर्ड में ऐतिहासिक परिवर्तन

पिछले तीन वर्षों में महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड का चेहरा पूरी तरह बदल गया है, और इस बदलाव का श्रेय समीर काज़ी को जाता है। उनके कार्यकाल में:

राज्य के प्रत्येक जिले में वक्फ कार्यालय की स्थापना की गई है।

प्रत्येक जिले में अब क्लास-१ अधिकारी नियुक्त हैं, जबकि पहले क्लर्क स्तर के कर्मचारी ही वक्फ के कार्य देखते थे।

कॉन्ट्रैक्ट पर भी बड़ी संख्या में कर्मचारियों की भर्ती की गई है।

पहले वक्फ बोर्ड लगभग ३०-४० कर्मचारियों के सहारे चलता था, अब यह संख्या २००-२५० तक पहुंच चुकी है।

जनशक्ति बढ़ने से लोगों को बेहतर सुविधा मिलने लगी है और काम समय पर होने लगे हैं।

राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि

वक्फ बोर्ड का वार्षिक राजस्व जो पहले ५ करोड़ से भी कम था, अब १० करोड़ के पार जा चुका है। यह वृद्धि जिलास्तर पर कामकाज सुचारु रूप से होने के कारण संभव हुई है।

राज्य में होंगे छह विभागीय कार्यालय

महाराष्ट्र में अब वक्फ बोर्ड के छह विभागीय कार्यालय स्थापित किए जाएंगे, जिनमें नागपुर-अमरावती के लिए एक कार्यालय, औरंगाबाद व नांदेड़ (जहां मराठवाड़ा में वक्फ संपत्तियां अधिक हैं) के लिए दो अलग कार्यालय बनाए जाएंगे।

इन विभागीय कार्यालयों के अंतर्गत चार उपमुख्य कार्यकारी अधिकारियों की नियुक्ति के प्रस्ताव के साथ कुल दस अधिकारियों की संरचना बनाई गई है, जो शीघ्र ही शासन को भेजी जाएगी।

सुर्खियां:

राज्य में वक्फ के छह विभागीय कार्यालय होंगे

वक्फ बोर्ड की आमदनी ५ करोड़ से बढ़कर १० करोड़ से अधिक हुई

जनशक्ति में बढ़ोत्तरी से कार्यो को मिली रफ्तार

जो बदलाव दस वर्षो में नहीं हो पाए, समीर काज़ी ने तीन वर्षो में कर दिखाए यह कदम न केवल बीड़ जिले के लिए गौरव की बात है, बल्कि राज्य के मुस्लिम समाज को उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में नई दिशा देगा।

हरियाणा और पंजाब में वक्फ बोर्ड की भूमिका: मेडिकल कॉलेज और शिक्षा में योगदान

विशेष रिपोर्ट

हरियाणा

मेवात इंजीनियरिंग कॉलेज - वक्फ बोर्ड के अंतर्गत

स्थापना वर्ष: २०१०

स्थान: नूंह जिला (पूर्व में मेवात), दिल्ली से लगभग ८० किलोमीटर दूर

प्रमुख पाठ्यक्रम:

बी.टेक - मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन

बी.वोकेशनल - ऑटोमोबाइल सर्विसिंग, रिन्यूएबल एनर्जी

डी.वोकेशनल - सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ऑटो सर्विसिंग

उद्देश्य: मेवात क्षेत्र के शैक्षणिक रूप से पिछड़े मुस्लिम छात्रों को गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा प्रदान करना, हालांकि कॉलेज सभी वर्गो के छात्रों के लिए खुला है।

आधिकारिक वेबसाइट: ाशलु.रल.ळप

हरियाणा में मेडिकल कॉलेज की स्थिति

हरियाणा वक्फ बोर्ड द्वारा अभी तक कोई मेडिकल कॉलेज सीधे तौर पर संचालित नहीं किया जा रहा है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं:

नई पहल:

यमुनानगर में १२०० करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी गई है, जिसमें १०० एमबीबीएस सीटें और ५००-बेड का अस्पताल शामिल है।

सरकार का लक्ष्य है कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोला जाए।

पंजाब

वक्फ बोर्ड की भूमिका - ज़मीन और सहयोग

मलेरकोटला मेडिकल कॉलेज:

पंजाब वक्फ बोर्ड ने इस कॉलेज के लिए २४.४४ एकड़ ज़मीन लीज पर दी थी।

यह कॉलेज १०० सीटों के साथ प्रस्तावित था, लेकिन भूमि विवादों और कानूनी अड़चनों के कारण कार्य में देरी हुई है।

संगरूर मेडिकल कॉलेज:

मलेरकोटला जैसी ही स्थिति यहाँ भी रही। भूमि विवादों के कारण कॉलेज निर्माण में रुकावटें आई हैं।

पंजाब वक्फ बोर्ड की स्कॉलरशिप योजना (मेडिकल छात्रों के लिए)

पात्रता:

पंजाब के निवासी मुस्लिम छात्र

वार्षिक पारिवारिक आय ८ लाख से कम

सरकारी या अर्ध-सरकारी कोटे में प्रवेश प्राप्त होना आवश्यक

वित्तीय सहायता:

MBBS/MD/MS/BDS/MDS/BVSc/MVSc: ६,००० प्रति माह

B.Tech/BUMS/B-MS/B.Sc.-griculture: ४,५०० प्रति माह

LLB/LLM/B.Sc. Nursing/B.Pharma: २,५०० प्रति माह

आवेदन प्रक्रिया:

आधार कार्ड, डोमिसाइल, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, और प्रवेश प्रमाण पत्र सहित दस्तावेज़ों के साथ आवेदन पंजाब वक्फ बोर्ड कार्यालय में जमा किया जाता है।

विवरण हेतु वेबसाइट: लुिरषिं.ळप

निष्कर्ष

हरियाणा और पंजाब में वक्फ बोर्ड द्वारा प्रत्यक्ष रूप से मेडिकल कॉलेज का संचालन फिलहाल नहीं किया जा रहा है, लेकिन वक्फ बोर्ड की भूमिका ज़मीन उपलब्ध कराने, शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना में सहयोग और छात्रवृत्ति के माध्यम से महत्वपूर्ण रही है। आने वाले समय में इन प्रयासों से मुस्लिम समाज के लिए मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है।

दिगंबर जैन मंदिर गिराने की घटना पूर्व नियोजित साजिश; 'बुलडोज़र सरकार' जिम्मेदार-वर्षा गायकवाड़

जैन समाज का विलेपार्ले में विराट मोर्चा, मूर्तियों और धर्मग्रंथों का भी किया गया अपमान

रिपोर्ट: जमीर काज़ी, मुंबई

मुंबई: विलेपार्ले (पूर्व) स्थित दिगंबर जैन मंदिर को लेकर चल रहे विवाद के बीच एक बड़ा आरोप सामने आया है। मंदिर से जुड़ा मामला न्यायालय में लंबित होने के बावजूद बीएमसी अधिकारियों ने बिना अदालती निर्णय की प्रतीक्षा किए मंदिर को ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई में जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों, जिनवाणी तथा अन्य पवित्र धार्मिक ग्रंथों का घोर अपमान किया गया। इस घटना की निंदा करते हुए मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद वर्षा गायकवाड़ ने इसे एक पूर्व नियोजित साजिश करार देते हुए भाजपा-शिवसेना (शिंदे गुट) गठबंधन की 'बुलडोज़र सरकार' को इसका जिम्मेदार ठहराया है।

इस घटना के विरोध में संपूर्ण जैन समाज की ओर से विलेपार्ले में एक विराट मोर्चा निकाला गया। इस मोर्चे में स्वयं शामिल होकर खा. गायकवाड़ ने जैन समुदाय की मांगों का समर्थन किया और बीएमसी अधिकारियों से जवाब भी तलब किया।वर्षा गायकवाड़ ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि जब उन्होंने महानगरपालिका आयुक्त भूषण गगराणी से संपर्क किया, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि उसी स्थान पर पुनः दिगंबर जैन मंदिर का निर्माण किया जाएगा। इससे पूर्व गायकवाड़ ने मंदिर स्थल का दौरा किया और मंदिर प्रबंधन समिति तथा पीड़ित जैन समाज के सदस्यों से भेंट की। मंदिर समिति के अनुसार, जिस स्थान पर मंदिर था, वहां एक होटल मालिक बार खोलना चाहता है और इसी कारण से बुलडोज़र चलवाया गया। समिति ने इस पर गहरी आपत्ति जताई है और इसे जैन समाज की आस्था पर सीधा प्रहार बताया है।

यह मामला अब न केवल धार्मिक भावनाओं से जुड़ा है, बल्कि प्रशासनिक मनमानी और सांप्रदायिक सद्भाव पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रहा है।

नकली पनीर अब एफडीए की निगरानी में

होटल और दुकानों के लाइसेंस होंगे रद्द-खाद्य एवं औषधि मंत्री नर्हरी झिरवाल की चेतावनी

मुंबई, १९ अप्रैल (अज़ीज़ अइजाज़)

खाद्य एवं औषधि प्रशासन (ऋ्ऊ-) ने नकली पनीर या उसके जैसे दिखने वाले पदार्थ का उपयोग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन मंत्री नर्हरी झिरवाल ने कहा है कि अगर कोई व्यापारी नकली पनीर जैसी वस्तु बेचता पाया गया, तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।

मंत्री झिरवाल ने कहा कि पनीर एक लोकप्रिय खाद्य सामग्री है और बाज़ार में इसकी भारी मांग है, विशेषकर छोटे बच्चों में। लेकिन हाल ही में की गई जांच में सामने आया है कि कुछ स्थानों पर नकली पनीर या उससे मिलते-जुलते पदार्थो का उपयोग करके ग्राहकों को धोखा दिया जा रहा है। ऐसे दुकानदारों और होटल व्यवसायियों के खिलाफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट २००६, और उसके अंतर्गत २०११ एवं २०२२ के नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

ग्राहकों को दी जानी होगी पूरी जानकारी:

फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स (लेबलिंग एंड डिस्प्ले) रेगुलेशन २०२० के अनुसार, विक्रेताओं को अपने उत्पादों के सभी घटक और पोषण संबंधी जानकारी ग्राहकों को देना अनिवार्य है। होटल, रेस्तरां, कैटरिंग सेवा और फास्ट फूड विक्रेताओं को अपने मेनू कार्ड, डिस्प्ले बोर्ड और ऑर्डर मशीनों पर स्पष्ट जानकारी देनी होगी।

गुणवत्ता से समझौता नहीं:

मंत्री झिरवाल ने कहा कि खाद्य एवं औषधि प्रशासन उपभोक्ताओं की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है और खाने की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि रेस्तरां और फास्ट फूड विक्रेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए गए हैं यदि वे उपभोक्ताओं को धोखा देते हुए नकली पनीर बेचते पाए जाते हैं।

निरीक्षण और कार्रवाई के आदेश:

ऋ्ऊ- ने सभी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने क्षेत्र में पनीर के एनालॉग (नकली पनीर) बेचने वालों के खरीद और बिक्री के बिलों की जांच करें। कम से कम १० संस्थानों की पूरी तरह से जांच कर नमूने लेकर आवश्यकतानुसार खाद्य सामग्री जब्त करने का आदेश दिया गया है।

यदि पाया गया कि होटल, रेस्तरां, फास्ट फूड विक्रेता या कैटरर नकली पनीर बेच रहे हैं, तो उनके लाइसेंस फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट २००६ और लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन रेगुलेशन २०११ के अंतर्गत तत्काल निलंबित किए जाएंगे।

क्या है नकली पनीर (पनीर एनालॉग)?

नकली पनीर या पनीर एनालॉग देखने और स्वाद में असली पनीर जैसा होता है, लेकिन इसे दूध से नहीं, बल्कि वनस्पति तेल और स्टार्च जैसे पदार्थो से बनाया जाता है। यह असली पनीर से सस्ता होता है, जिससे होटल और खानपान उद्योग इसे आकर्षक विकल्प मानते हैं। लेकिन इसे खाने से दिल की बीमारियाँ और अन्य स्वास्थ्य समस्याएँ हो सकती हैं। असली पनीर की बनावट ठोस होती है, जबकि नकली पनीर की बनावट रबड़ जैसी या बहुत मुलायम होती है।

उर्दू दैनिक तामीर के २५ वे साल में क़दम रखने पर एक और पेशकश

देश में थोप दी गई है तानाशाही, संविधान और अल्पसंख्यकों के अस्तित्व को खत्म करने की कोशिश-हर्षवर्धन सपकाळ

‘डरो मत’ का संदेश अपनाएँगे, एकता और अखंडता की मशाल लेकर आगे बढ़ेंगे: माइनॉरिटी यूथ पार्लियामेंट में हर्षवर्धन सपकाळ का संबोधन

पुणे: महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ ने कहा है कि देश में लोकतंत्र और संविधान को दरकिनार कर तानाशाही थोपी जा रही है। आज देश का हर तबका डर और दबाव के साए में जीने को मजबूर है। सत्ता में बैठी ताकतें समाज में भय का माहौल बना रही हैं, लेकिन हमें घबराना नहीं है, बल्कि एकता और राष्ट्रीय अखंडता की मशाल के साथ आगे बढ़ना है। राहुल गांधी की 'भारत जोड़ो यात्रा' के दौरान दिया गया संदेश 'डरो मत' आज हर नागरिक का मूल मंत्र होना चाहिए।

सपकाळ पुणे में आयोजित 'माइनॉरिटी यूथ पार्लियामेंट' कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश में संविधान को अप्रभावी बनाने और अल्पसंख्यकों को हाशिए पर लाने की साजिशें हो रही हैं। अल्पसंख्यक समुदाय, किसान, बेरोजगार युवा, महिलाएं,

घरेलू महिलाएं, यहां तक कि छत्रपति शिवाजी महाराज के अनुयायियों तक में भी डर का माहौल है। हर तबका महंगाई, असुरक्षा और संवैधानिक अधिकारों के हनन से परेशान है, लेकिन यह बेहद दुखद है कि जो लोग छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे महानायकों का अपमान करते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही।

उन्होंने जोर देकर कहा कि बहुसंख्यक समाज को अल्पसंख्यकों की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन वर्तमान परिस्थिति इसके विपरीत है। ऐसे हालात का मुकाबला केवल एकता, समरसता और राष्ट्रीय अखंडता के जज़्बे से ही किया जा सकता है। अपने भाषण के अंत में सपकाळ ने कहा:

नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं,
सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, कश्तियों को बदलने की ज़रूरत नहीं,
रुख़ को बदलो तो किनारे बदल जाते हैं।

कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के संभावित गठबंधन पर कहा कि अगर ये दोनों एक साथ आते हैं, तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार महाराष्ट्र को नुकसान पहुँचा रही है, उद्योग राज्य से बाहर जा रहे हैं और महायुति की नीतियाँ महाराष्ट्र के हितों के खिलाफ हैं। सपकाळ ने कहा कि महाराष्ट्र की संस्कृति शिव, शाहू, फुले और आंबेडकर के विचारों पर आधारित है, जहाँ सभी को साथ लेकर चलने की परंपरा रही है, लेकिन बीजेपी इस परंपरा को तोड़ने का प्रयास कर रही है। राज ठाकरे के हालिया बयानों से भी यह बात साबित होती है। हम कांग्रेस वाले भारत जोड़ने वाले लोग हैं, परिवार तोड़ने वाले नहीं। अगर दो परिवार करीब आ रहे हैं तो इसका विरोध नहीं, बल्कि स्वागत किया जाना चाहिए।

बीड़ में शिवसेना नेता सचिन मुळूक के निवास पर मंत्री उदय सामंत की विशेष भेंट

बीड़ जिले में मुळूक के साथ शिवसेना नेतृत्व मजबूती से खड़ा है-मंत्री उदय सामंत

बीड़ (प्रतिनिधि):

शिवसेना पर चाहे कितनी भी विपत्तियाँ आएं, उन्हें सामना करने के लिए हम सभी निष्ठावान कार्यकर्ता पूरी तरह तैयार हैं। बीड़ जिले में शिवसेना नेतृत्व हमेशा जिल्हा प्रमुख सचिन मुळूक के साथ मजबूती से खड़ा है, ऐसा विश्वास उद्योग मंत्री उदय सामंत ने व्यक्त किया।

बीड़ दौरे पर आए शिवसेना नेता एवं राज्य के उद्योग मंत्री उदय सामंत ने जिल्हा प्रमुख सचिन मुळूक के निवास पर जाकर उनसे सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर मुळूक परिवार की ओर से सामंत का स्वागत किया गया।

अपने वक्तव्य में सामंत ने बताया कि वे स्वयं जब शिवसैनिक के रूप में सक्रिय थे, तभी से उनका और मुळूक का आत्मीय संबंध रहा है। शिवसेना के प्रति निष्ठा के चलते ही वे आज उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में उद्योग मंत्री के रूप में कार्यरत हैं।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पूर्व शिवसैनिक होने के बावजूद आज भी उनका मुळूक के प्रति स्नेह और सम्मान जरा भी कम नहीं हुआ है। बीड़ में आयोजित निवेश परिषद के सिलसिले में आए उदय सामंत ने सचिन मुळूक के निमंत्रण को स्वीकारते हुए प्रोटोकॉल की परवाह किए बिना उनके निवास पर जाकर अपनी नजदीकी का परिचय दिया।इस भेंट के दौरान सांसद संदीपान भुमरे, छत्रपति संभाजीनगर के जिल्हा प्रमुख राजेंद्र जंजाळ, बीड़ के पहले शिवसेना नगराध्यक्ष शिवलाल मुळूक, जिल्हा प्रमुख सचिन मुळूक और मुळूक परिवार के अन्य सदस्य उपस्थित थे। मंत्री सामंत ने कहा कि सचिन मुळूक जैसे निष्ठावान कार्यकर्ताओं की मजबूत उपस्थिति शिवसेना और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के लिए वज्रमुठ (लोहे की मुट्ठी) जैसी है। इस अवसर पर शिवसेना जिल्हा प्रमुख अनिल जगताप, स्वप्निल गलधर समेत कई नेता उपस्थित थे।

लोकाशा भूषण पुरस्कार की धनराशि गौशाला को दान कर राधेश्याम चांडक (भाईजी) ने पेश की मिसाल

बीड (प्रतिनिधि):

बुलढाणा अर्बन बैंक के संस्थापक अध्यक्ष माननीय राधेश्यामजी चांडक (भाईजी) को हाल ही में बीड में आयोजित एक कार्यक्रम में सहकार क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए राज्य के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजित पवार के हाथों लोकाशा भूषण पुरस्कार' से सम्मानित किया गया। इस सम्मान के तहत उन्हें प्रशस्ति पत्र, स्मृतिचिन्ह और एक लाख रुपये की नगद राशि प्रदान की गई।

इस अवसर पर राधेश्यामजी चांडक ने अपने मनोगत में घोषणा की कि वे यह संपूर्ण धनराशि, जिसमें उन्होंने स्वयं के २५ हजार रुपये भी जोड़े, बीड जिले के नामलगाव फाटा स्थित साध्वी प्रीतीसुधाजी गोरक्षण केंद्र को दान करेंगे।

अपनी इस घोषणा को अमल में लाते हुए उन्होंने आज २९ क्विंटल सरकी पेंड (गायों के चारे के लिए) गौशाला को प्रदान की और समाज के सामने एक अनुकरणीय उदाहरण

प्रस्तुत किया। उनके इस निर्णय की सर्वत्र सराहना की जा रही है। उल्लेखनीय है कि स्वयं की गौशाला बुलढाणा में होते हुए भी उन्होंने सहायता बीड की गौशाला को दी, जहाँ २०० से अधिक गायों की सेवा की जाती है।

इस अवसर पर राधेश्यामजी चांडक ने बीडवासियों से अपील की कि जिले में मौजूद गौशालाओं को गुढ़, पेंड और चारा जैसी चीजें प्रदान करें। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में गाय का विशेष महत्व है, और गोरक्षा में किया गया योगदान कभी व्यर्थ नहीं जाता।

इस अवसर पर बुलढाणा अर्बन बैंक के बीड विभागीय प्रबंधक संजय नानासाहेब देशमुख, शाखा प्रबंधक सतीश जाधव, बैंक के कर्मचारी, गोसेवक गौतम खटोड़ एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे।

गौशाला के अध्यक्ष विजयराज बंब की उपस्थिति में पेंड गौशाला को सौंपा गया, और पहले ही दिन वहाँ की गायों को १५० किलो पेंड का गोग्रास (भोजन) दिया गया।

अनिलदादा जगताप की उपस्थिति में बड़ी संख्या में युवाओं का शिवसेना में प्रवेश!

बीड (प्रतिनिधि):

हिंदुहृदयसम्राट बाला साहेब ठाकरे और धर्मवीर आनंद दिघे साहेब के विचारों से प्रेरित होकर तथा महाराष्ट्र राज्य के कर्मठ उपमुख्यमंत्री एवं शिवसेना के मुख्य नेता माननीय एकनाथजी शिंदे साहेब और संसदरत्न सांसद डॉ. श्रीकांत शिंदे साहेब के नेतृत्व में चल रही शिवसेना की मजबूत कार्यपद्धति से प्रभावित होकर, बीते १९ अप्रैल को दोपहर १ बजे बीड के जालना रोड स्थित शिवसेना मध्यवर्ती कार्यालय में असंख्य युवाओं ने शिवसेना में सार्वजनिक रूप से प्रवेश किया।

यह प्रवेश शिवसेना जिल्हा प्रमुख अनिलदादा जगताप, ओबीसी वी.जे.एन.टी सेना महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष बालासाहेब किसवे, राज्य संपर्क प्रमुख किरण चव्हाण, जिल्हा प्रमुख मनोज चव्हाण और जिल्हा

संघटक दगडू दादा गायकवाड के नेतृत्व में हुआ। प्रवेश करने वालों में अशोक दुधाळ, सूरज गायकवाड, अमित गायकवाड, शुभम आखाडे, संदेश सावंत, विशाल उबाळे, दामोदर डोळस, किशोर जाधव, भरत जाधव, सुमित जाधव, वसंत जाधव, प्रशांत दुधाळ, प्रितम दुधाळ, दीपक भराटे, महेश नेवडे, गोपाल आखाडे, सुशील दुधाळ, औदुंबर दुधाळ, नितिन शेवाळे, दत्ता राऊत, विनोद गायकवाड, रवि दुधाळ, अविनाश कुर्हाडे, सोहेल गायकवाड, तेजस नाळे, सोनू सुरवसे, अविष्कार दुधाळ, अनय गायकवाड, राम अंकुशे, सचिन अंकुशे, श्याम अंकुशे, प्रतिक दुधाळ, निवास रोकडे, संघर्ष डोंगरे, सौरभ राऊत, बबलू घुमरे, अतुल जगताप, शैलेश आगलावे और दीपक बोबडे जैसे अनेक युवा शामिल थे।

इस अवसर पर शिवसेना जिल्हा प्रमुख अनिलदादा जगताप, ओबीसी वी.जे.एन.टी सेना जिल्हा प्रमुख मनोज चव्हाण और संघटक दगडू दादा गायकवाड ने सभी युवाओं को भगवा झंडा सौंपकर उनका शिवसेना में स्वागत किया। अनिलदादा जगताप ने अपने संबोधन में कहा कि बाला साहेब ठाकरे के विचारों को आगे बढ़ाते हुए एकनाथ शिंदे साहेब ने मुख्यमंत्री के रूप में आम जनता के लिए अनेक जनकल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की है और खुद को एक जननेता के रूप में स्थापित किया है। उनके नेतृत्व को मजबूत बनाने के लिए सभी जाति-धर्म के कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर काम करना जरूरी है। ओबीसी वी.जे.एन.टी सेना के जिल्हा प्रमुख मनोज चव्हाण और संघटक दगडू गायकवाड ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि अठरा पगड जातियों की वज्रमुठ (लोहे की मुट्ठी) बनाकर एकनाथ शिंदे साहेब की ताकत बढ़ाई जाएगी।

इस अवसर पर शिवसेना, युवासेना के पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे।

चुनी हुई सेंसरशिप क्यों?-कल्पना पांडे

‘द स्टोरीटेलर’ जैसी संवेदनशील और अर्थपूर्ण फिल्में बनाने वाले राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अनंत महादेवन के निर्देशन में बनी फिल्म फुले’ प्रदर्शन से पहले ही विवादों में घिर गई है। यह फिल्म मूलतः ११ अप्रैल २०२५ को रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन महाराष्ट्र की कुछ ब्राह्मण संगठनों द्वारा जातिगत भेदभाव को बढ़ावा देने के आरोप लगाए जाने के चलते इसे २५ अप्रैल २०२५ तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।

कल्पना पांडे
kalpana2810283gmail.com
मो.नं: ९०८२५७४३१५

भारत में लड़कियों के लिए पहले स्कूल की स्थापना करना और तथाकथित पिछड़ी जातियों के विकास के लिए काम करना-यह सब फुले दंपत्ति के सामाजिक न्याय के सिद्धांत का मूल है। फिल्म में प्रतीक गांधी ने ज्योतिराव फुले और पत्रलेखा ने सावित्रीबाई फुले की भूमिका निभाई है। यह फिल्म १९वीं सदी के भारत में शिक्षा और सामाजिक समानता के लिए किए गए उनके क्रांतिकारी प्रयासों को दर्शाती है, जिसमें १८४८ में लड़कियों के लिए देश का पहला स्कूल खोलना शामिल है। अनंत महादेवन के निर्देशन में बनी इस फिल्म का उद्देश्य जाति और लिंग भेदभाव के खिलाफ उनकी अथक लड़ाई को उजागर करना है।

ब्राह्मण संगठनों के आपत्ति के बाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (उइत्रऊ) ने फिल्म में कुछ बदलावों का सुझाव दिया है। उइत्रऊ ने 'मांग', 'महार', 'पेशवाई' जैसे जातिगत संदर्भ वाले शब्दों को हटाने या बदलने की सिफारिश की है। इसी तरह, ३००० साल की गुलामी जैसे संवाद को कई वर्षों की गुलामी में बदलने का सुझाव दिया गया है। वास्तव में, यह फुले की विचारधारा की ऐतिहासिक सच्चाई को कमज़ोर करने का प्रयास है। यह संशोधन उनकी विचारधारा और वंचित समुदायों के संघर्ष के साथ अन्याय है। कई सामाजिक संगठनों ने इस फैसले की आलोचना की है और उइत्रऊ पर पक्षपात का आरोप लगाया है।

सबसे पहला सवाल यह उठता है कि क्या हमारे देश में फिल्मों की मंजूरी के लिए अलग-अलग मानदंड हैं? द केरल स्टोरी' और द कश्मीर फाइल्स' जैसी विवादास्पद फिल्मों को आसानी से उइत्रऊ की मंजूरी मिल जाती है, जबकि सामाजिक सुधार और जातिगत असमानता को उजागर करने वाली फुले' जैसी फिल्मों को बदलाव और देरी का सामना करना पड़ता है। महात्मा फुले की जयंती ११ अप्रैल को होती है और फिल्म की रिलीज़ उस अवसर से जुड़ी थी, जिसका व्यावसायिक लाभ भी होता। ऐसे में रिलीज़ में देरी और संशोधन यह स्पष्ट करते हैं कि उइत्रऊ हर फिल्म पर समान मानदंड लागू नहीं करता। जो फिल्में एक विशेष विचारधारा के समर्थन में होती हैं, उन्हें छूट दी जाती है, जबकि चुनौती देने वाले विषयों पर रोक लगाई जाती है। यह उइत्रऊ की निष्पक्षता पर सवाल उठाता है और रचनात्मक स्वतंत्रता व ऐतिहासिक सच्चाई को दबाने का प्रयास लगता है।

दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि भारत में जाति एक अत्यंत संवेदनशील विषय है। आज भी जातिगत भेदभाव मौजूद है। फुले' जैसी फिल्में जो इस मुद्दे को सामने लाती हैं, उनके खिलाफ उइत्रऊ का रवैया बताता है कि वह राजनीतिक दबाव या सामाजिक स्थिरता के नाम पर काम कर रहा है। फुले' पर कड़ी शर्तें लागू करना यह दर्शाता है कि उइत्रऊ सामाजिक सुधारों को नियंत्रित करना चाहता है, जबकि विभाजनकारी विचारों को अनदेखा करता है।

तीसरा बिंदु यह है कि फुले' को समय पर रिलीज़ न होने में ब्राह्मण संगठनों की शिकायतों की अहम भूमिका रही है। इन संगठनों का मानना है कि यह फिल्म ब्राह्मण समुदाय को नकारात्मक रूप में दर्शाती है, जिससे वे विलेन के रूप में दिखते हैं या उन पर अन्याय के आरोप लगाए गए हैं। इन शिकायतों के चलते उइत्रऊ ने फिल्म पर सवाल खड़े किए, कुछ दृश्यों और संवादों पर आपत्ति जताई और बदलाव का सुझाव दिया, जिससे फिल्म की रिलीज़ में देरी हुई। फिल्म निर्माताओं का कहना है कि फिल्म ऐतिहासिक रूप से सटीक है, और इसमें ऐसे ब्राह्मण पात्र भी हैं जो फुले दंपत्ति के काम का समर्थन करते हैं। फिर भी, उइत्रऊ ने ब्राह्मण संगठनों की आपत्तियों को प्राथमिकता दी और फिल्म निर्माताओं के ऐतिहासिक तथ्यों को नजरअंदाज कर जाति से संबंधित शब्दों को बदलने पर ज़ोर दिया। इससे उइत्रऊ की निष्पक्षता संदिग्ध प्रतीत होती है, क्योंकि ऐसा लगता है कि वह एक खास समूह की भावनाओं को अधिक महत्व देता है और कलाकारों के दृष्टिकोण की अनदेखी करता है।

इसका सीधा असर फिल्म के मूल संदेश और दर्शकों के अधिकारों पर पड़ता है। सवाल उठता है कि क्या उइत्रऊ स्वतंत्र रूप से निर्णय ले रहा है या संगठनों के दबाव में काम कर रहा है? अगर उइत्रऊ दबाव में ऐतिहासिक सच्चाई और रचनात्मक दृष्टिकोण को बदलने पर मजबूर होता है, तो यह रचनात्मक स्वतंत्रता के साथ अन्याय है।

चौथा महत्वपूर्ण पहलू रचनात्मक स्वतंत्रता का है। फुले' का मूल उद्देश्य शोषण आधारित व्यवस्था में सुधार करना था, इसलिए उस दौर में उन्हें भारी विरोध और सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ा। आज भी, फिल्म में संशोधन उनकी ऐतिहासिक सच्चाई को बदल देगा। इससे न केवल फिल्म निर्माताओं की रचनात्मक अभिव्यक्ति प्रभावित होगी, बल्कि दर्शकों के जानकारी के अधिकार का हनन भी होगा।

चाहे फिल्म को मंजूरी मिले या नहीं, एक बात तय है-यह फिल्म हमारे सामाजिक इतिहास का दर्पण है जो वास्तविक सच्चाई को सामने ला रही है। इसमें लड़कियों की शिक्षा के लिए संघर्ष, जाति की दीवारें तोड़ने वाला शिक्षक, ब्राह्मणवादी वर्चस्व पर आधारित व्यवस्था, सामाजिक बहिष्कार और धार्मिक उत्पीड़न की कहानियाँ शामिल हैं।

महात्मा फुले का कार्य उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले के योगदान के बिना अधूरा है। उन्होंने एक अशिक्षित बालिका को पढ़ाया और देश की पहली महिला शिक्षिका के रूप में स्थापित किया। सावित्रीबाई ने सामाजिक बहिष्कार और अपमान सहते हुए शिक्षा की ज्योति जलाए रखी।

फुले ने जाति आधारित शिक्षा व्यवस्था की दीवारें गिराईं और अछूत, दलित व शूद्र बच्चों के लिए स्कूल खोले। उनके स्कूलों में जाति नहीं पूछी जाती थी, जो उस दौर में क्रांतिकारी था। उन्होंने गुलामगिरी' जैसी किताबों में जातिगत व्यवस्था की पोल खोली और ब्राह्मणवाद पर सीधा प्रहार किया।

उन्होंने कहा, जब तक समाज शिक्षित नहीं होगा, वह गुलाम ही रहेगा। फुले द्वारा शुरू किया गया यह आंदोलन रंग-भेद वाली व्यवस्था के खिलाफ था, जिसे शक्तिशाली वर्ग का समर्थन प्राप्त था। समाज ने उन्हें बहिष्कृत किया। सावित्रीबाई का अपमान हुआ, उन पर गंदगी फेंकी गई, फिर भी वे नहीं रुकीं। उन्होंने धार्मिक आतंक का भी सामना किया और भगवान, धर्म और पूजा के तरीकों पर सवाल उठाए।

उन्होंने कहा, भगवान ने इंसान को नहीं बनाया, बल्कि भगवान खुद इंसान की कल्पना है। इन विचारों के लिए उन्हें नास्तिक और धर्म विरोधी कहा गया, फिर भी वे अपने मार्ग से विचलित नहीं हुए।

महात्मा फुले का कार्य सिर्फ शिक्षा तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जिससे सामाजिक समानता का नया मार्ग प्रशस्त हुआ। विधवाओं की पुनर्विवाह, महिलाओं को गर्भपात का अधिकार, लड़कियों की शिक्षा की ज़रूरत, कृषि में शोषण और ब्राह्मण पुजारी वर्ग का वर्चस्व-इन सभी मुद्दों पर उन्होंने लेखन और कार्य किया।

सत्यशोधक समाज ने विवाह, नामकरण, अंतिम संस्कार जैसे धार्मिक कृत्य ब्राह्मणों के बिना करना शुरू किया। जाति आधारित भेदभाव छोड़कर एक साथ भोजन और सार्वजनिक आयोजन की परंपरा शुरू की। सभी जातियों के लोगों ने सत्यशोधक' के रूप में अपनी पहचान बनाई।

सत्यशोधक समाज ने पहली बार दलित, शूद्र, महिलाएँ-इन सभी को आत्मीयता और सम्मान देने वाला सामाजिक मंच प्रदान किया। समाज में समान अधिकार की मांग शुरू हुई।महात्मा फुले की उम्र और स्वास्थ्य बिगड़ने के बावजूद समाज के लिए उनकी ऊर्जा कम नहीं हुई। उनकी मृत्यु के बाद भी सत्यशोधक समाज की प्रेरणा जारी रही।

बाद में शाहू महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर और पेरियार जैसे नेताओं ने सत्यशोधक विचारधारा से प्रेरणा ली। आज भी जाति आधारित हत्याएं, अंधविश्वास और आदिवासियों, महिलाओं, दलितों और ओबीसी के अधिकारों पर हमले होते हैं।

निर्देशक अनंत महादेवन ने फिल्म का बचाव करते हुए कहा है, मेरी फिल्म का कोई एजेंडा नहीं है। यह भारतीय समाज को बदलने वाले सामाजिक सुधारकों के प्रति सच्ची सिनेमाई श्रद्धांजलि है।उनके अनुसार, फिल्म का उद्देश्य भड़काना नहीं, बल्कि शिक्षित करना और प्रेरणा देना है। फुले वाडा' सिर्फ एक फिल्म नहीं है; यह भारत में जातिगत बहसों के केंद्र में उठती बेचैनी है।

फुले का कार्य शैक्षणिक रूप से सराहा जाता है, फिर भी उनके सामाजिक विचारों को मीडिया में दिखाने के प्रयासों को अब भी रोका जा रहा है।

जातिगत असमानता को चुनौती देकर दलित और वंचित समुदायों को सशक्त बनाने की जो निरंतर कोशिश फुले दंपत्ति ने की, वह आज भी प्रासंगिक है। शिक्षा, समानता और न्याय की ओर उठाया गया हर कदम महात्मा फुले की प्रेरणादायी विरासत को झलकाता है।

महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले द्वारा प्रस्तुत किया गया सत्यशोधक' मार्ग आज भी अनेक विचारों को दिशा देता है।

दैनिक भारत की तामीर अखबार के मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक काजी मखदूम शफीउद्दीन ने आरएम प्रिंटरर्स, बार्शी रोड, बीड 431122 महाराष्ट्र में मुद्रित कर के दैनिक तामीर, नगर परिषद परिसर, बशीर गंज, बीड, महाराष्ट्र कार्यालय से प्रकाशित किया है। मोबाइल : 9270574444 ईमेल : hinditameer@gmail.com वेबसाइट : www.dailytameer.com
daily Bharat ki tameer newspaper owner printer publisher editor Quazi makhdoom shafiuddin has printed at RM printers barshi road beed 431122 Maharash-tra at published at office daily tameer nagar parishad complex Bashir gunj beed Maharashtra. Mobile : 9270574444 Email : hinditameer@gmail.com Website : www.dailytameer.com